

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2011/आषाढ़ 9, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 81  
No. 110] DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2011/ASADHA 9, 1933 [N.C.T.D. No. 81

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2011

फा. सं. 1(4)/एफएएस/डब्ल्यूडीएम/डब्ल्यूसीडी/2005-06/7951-961.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राजधानी क्षेत्र, दिल्ली गरीब विधवा महिला की पुत्री एवं अनाथ लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता नियमावली, 2006 के नियमों में निम्न संशोधन करती है।

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

- यह नियम गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री एवं अनाथ लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता संशोधन नियम, 2011 कहे जायेंगे।
- यह नियमावली चालू वित्त वर्ष से लागू माना जायेगा।

2. गरीब विधवा महिला की पुत्री एवं अनाथ लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता नियमावली, 2006 के नियम 3 में निम्न प्रस्थापित किया जाता है।

**नियम 3 :** प्रार्थी की आर्थिक सहायता हेतु जिला समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास अधिकारी या संयुक्त निदेशक (एफएएस) योजना के अर्न्तगत भुगतान के सत्यापन तथा स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी होगा। विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों के मामले में सक्षम अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करके आवेदक की विषय वस्तु के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर सकता/सकती है। केवल संदेहास्पद मामलों में तथा जो आवेदक पेंशन नहीं पा रहे हैं उनके मामले में सक्षम अधिकारी विभागीय अन्वेषकों के माध्यम से जांच/सत्यापन करा सकते हैं।

3. संदर्भित नियमावली, 2006 के नियम 4 में एक मुश्त सहायता राशि "बीस हजार" के स्थान पर "पच्चीस हजार" प्रस्थापित किया जाता है।

4. संदर्भित नियमावली, 2006 के नियम 8 में "निदेशक समाज कल्याण" के स्थान पर "निदेशक महिला एवं बाल विकास" प्रस्थापित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
राजीव काले, निदेशक

**DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT  
NOTIFICATION**

Delhi, the 30th June, 2011

**F.No. 1(4)/FAS/WDM/WCD/2005-06/7951-961.**—The Government of NCT of Delhi hereby makes the rules to amend Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls Rules, 2006.

**1. Short title, extent and commencement:**

- (1) Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls Amendment Rules, 2011.
- (2) They shall come into force from the current financial year.

2. In the Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls Rules, 2006 therein after referred as the said Rules, in Rule 3 the following shall be substituted :

**Rule 3:** The District, Social Welfare/Women and Child Development Officers or Jt. Director, FAS shall be the competent authority for verification and sanction of the payment under the scheme. In case of existing widows who are getting pension, the competent authority may satisfy him/herself about the contents of the application by screening the documents submitted by the applicant. In doubtful cases only, the competent authority may get the verification conducted through the departmental investigators. In case of non-pensioners, the competent authority may get such verification done as deemed necessary through departmental investigators.

3. In the said Rules, in rule 4 the words "Twenty Five Thousand" shall be substituted for the words "Twenty Thousand".

4. In the said Rules, in Rule 8 the words "Director Women and Child Development" shall be substituted for the words "Director Social Welfare".

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi.

RAJIV KALE, Director

**परिवहन विभाग**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 30 जून, 2011

**फा. सं. एनडब्ल्यूजेड/1/88/परि./2007/74.**—केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खंड (घ) के प्रावधानों तथा सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सा.का.नि. 221(अ) के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (क) तथा धारा 2 के खंड (41) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि संस्था केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 11 के उप-नियम (1) में उल्लिखित मामलों की पर्याप्त जानकारी एवं ज्ञान रखने का प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा प्राधिकृत होगी।

उक्त प्राधिकार निम्न शर्तें पूरी करने पर ही वैध होगा :—

- (i) वह कोई भी संस्था, जो समुचित विधिक प्राधिकरण के साथ शैक्षणिक सोसायटी/गैर-सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत हो आवेदन कर सकती है।
- (ii) संस्था के पास मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल चलाने का पाँच वर्ष का अनुभव हो।
- (iii) संस्था के सड़क सुरक्षा पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पाँच वर्ष का अनुभव हो।
- (iv) प्रारम्भ से ही स्वच्छ रिकार्डधारी हो। उसने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों एवं संस्था विरुद्ध नियम के प्रावधानों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न किया हो।
- (v) पिछले तीन वर्षों से संस्था में वार्षिक वित्तीय लेन-देन 25 लाख रुपये हो या अंतिम वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये हो।
- (vi) संस्था के पास परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित प्राथमिक कौशल परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर पद्धति की सहायता से कौशल परीक्षा के आयोजन की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित प्राथमिक कौशल परीक्षा से संबंधित पर्याप्त प्रश्न बैंक हो। संस्था का प्रशिक्षु लाइसेंस मूल्यांकन सॉफ्टवेयर सत्यता/विश्वसनीयता के लिए परिवहन विभाग के एमएलओ/निरीक्षक द्वारा प्रति परीक्षण होना चाहिए।
- (vii) कम्प्यूटर सिस्टम में सुरक्षा विशेषताएँ जैसे आवेदन के फोटो स्कैन, बायोमैट्रिक एवं उंगलियों के निशान होने चाहिए तथा परीक्षा के प्रारम्भ और समाप्त होने के समय सहित प्रत्येक परीक्षा पेपर के रिकार्ड के रख-रखाव की सुविधा हो।

- (viii) संस्था को यथानिर्धारित प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा। हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी आटो मोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी व्यक्ति हो।
  - (ix) परिवहन विभाग के संबंधित पदनामिक, जोन निरीक्षक द्वारा संस्था का निरीक्षण होगा अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा विधिवत प्राधिकृत अन्य अधिकारी।
  - (x) संस्था के पास कम से कम सात दिनों की रिकार्डिंग के रखरखाव की सुविधा सहित परीक्षा कक्ष में सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाने के लिए उचित प्रबंध होगा और परिवहन विभाग जिसमें एमएलओ कार्यालय भी शामिल है में स्टैटिक आई पी पत्र/इंटरनेट का साथ उपलब्ध कराना होगा।
  - (xi) कम से कम 5000 प्रमाण-पत्र जो कि संस्था द्वारा जारी किए गए हैं, परिवहन विभाग के एमएलओ/निरीक्षक द्वारा मूल्यांकन व प्रति प्रशिक्षण किए जाएंगे।
  - (xii) प्राधिकरण का आवेदन परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रफार्मा में लिया जाएगा।
  - (xiii) संस्था प्रत्येक दिन संक्षेप प्रशिक्षु लाइसेंस रिपोर्ट परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत करेगी। सभी एमएलओ को पासवर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता प्रमाणित कर सकें।
  - (xiv) टेस्ट का स्थान संबंधित क्षेत्रीय एमएलओ द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक जोन में केवल एक जोन ही प्राधिकृत होगा।
  - (xv) परिवहन विभाग संस्था द्वारा आयोजित टेस्ट की पूर्णता की जांच के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट नियुक्त कर सकता है, और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर दोषी संस्था पाई गई तो उसकी प्रमाणिकता किसी भी समय रद्द कर दी जाएगी।
  - (xvi) प्राधिकरण मोटर वाहन एक्ट एवं डीएमवीआर, 1993 के आधार पर बनाए व समय-समय पर संशोधित के अंतर्गत होगा।
- वह अधिसूचना पहली अधिसूचना संख्या 19(31)/परि./सचि./09/488, दिनांक 17 जुलाई, 2009 के स्थान पर होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
आर. के. वर्मा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त

#### TRANSPORT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2011

**F. No. NWZ/I/88/Tpt/2007/74.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 28 and clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with notification No. G.S.R. 221(E) dated 28th March, 2001 issued by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, and the provisions of clause (d) of sub-rule (2) of rule 11 of Central Motor Vehicle Rules, 1989, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby orders that Institutions will be authorized by the Government of National Capital Territory of Delhi, for the purpose of issuance of certificate of possession of adequate knowledge and understanding of the matters referred to in sub-rule (1) of rule 11 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

The said authorisation shall remain valid subject to the fulfilling of following conditions:

- (i) Any institution registered as Educational Society/NGO with the appropriate legal authority can apply.
- (ii) The institution should have experience of five years in running a motor driving training school.
- (iii) The institution should have experience of five years in road safety refresher training course.
- (iv) Must be a clean record holder since inception. There must not be any case of violation of provisions of Motor Vehicle Act 1988, and Rules against the institute.
- (v) Annual financial turnover of the institution should be Rs.25 lakh for last three consecutive years or 50 lakh for the last financial year.
- (vi) The institution should have the facility to conduct skill tests with the help of computer /software system having sufficient question bank relating to syllabus of preliminary skill test approved by Transport Department. The learner's license evaluation software of the institution should be cross-checked by MLO/Inspector of the Transport Department for correctness and fidelity.
- (vii) The computer system should further have security features like scan of photo, biometrics and finger print of the applicant and facility to maintain the record of each test paper along with the starting and end time of test.



- (viii) The institution should submit the details of signatory authorized by them to issue certificate as prescribed. The authorized signatory should be a person having degree in automobile/mechanical engineering.
- (ix) The institution will be subject to inspection by the designated Inspectors of concerned Zone of the Transport Department, or any other official duly authorized by Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi.
- (x) The institution should have proper arrangement for CCTV Cameras installed in the test room with facility to maintain the recording for at least seven days and access provided to the Transport Department including the MLO office with static IP address through internet.
- (xi) At least 5000 certificates issued by the institution should have been evaluated and cross-checked by MLO/Inspector of the Transport Department.
- (xii) Application for authorization will be made in the proforma prescribed by the Transport Department, National Capital Territory of Delhi.
- (xiii) The institution will submit daily online report of each Learning License test to the Transport Department, National Capital Territory of Delhi. All MLOs will be provided with password to verify the genuineness of the certificate issued by the institute.
- (xiv) Test venues will be inspected by the concerned Zonal MLO. Only one such venue will be authorized for each zone.
- (xv) Transport Department may appoint independent auditor to check the integrity of test conducted by the institution and on the basis of report if any discrepancy observed, recognition may be revoked at any time.
- (xvi) Authorization will be subject to Motor Vehicle Act and Rule framed thereunder and DMVR, 1993 as amended time-to-time.

This notification supersedes the earlier notification No. F. 19(31)/Tpt/Sectt./09/488 dated 17th July, 2009.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
R.K. VERMA, Pr. Secy-cum-Commissioner